अवैध कटान को लेकर उक्रांद हुआ मुखर

- नरेंद्र नगर के एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर की कार्यवाही की मांग

भास्कर समाचार सेवा

नरेंद्र नगर के एसडीएम को ज्ञापन सौंपते उक्रांद कार्यकर्ता।

देहरादून। नरेंद्र नगर के आसपास जंगलों के अवैध कटान को लेकर एसडीएम आशीष घिल्डियाल को उक्रांद की ओर से ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि नरेंद्र नगर ही नहीं पूरे उत्तराखंड में बाहरी कंपनियों और भूमाफियाओं द्वारा नरेंद्र नगर के आसपास जंगलों को अवैध ढंग कटान जारी है जो कि अत्यधिक खेदजनक है तथा पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाने की गैरकानूनी कार्यवाही है। पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। यदि अति शीघ्र पहाड़ों पर हो रही इस प्रकार की कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई गई तो इसके लिए बड़े आंदोलन की शुरुआत की जाएगी जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। अतः उच्च न्यायालय नैनीताल एवं एनजीटी में इसके विरुद्ध कानून कार्यवाही के लिए उचित कदम उठाया जाए। उन्होने कहा कि समय रहते अवैध कार्यवाही पर रोक लगाते हुए इस गैरकानूनी कार्यवाही में संलिप्त दोषियों तथा संरक्षण देने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें। धरना प्रदर्शन में शामिल वरिष्ट नेता रामेश्वरी चौहान, युद्धवीर चौहान, सुरेंद्र भंडारी केएस राणा, कुंवर सिंह राणा, ज्ञान सिंह रावत, मोहन भंडारी, राजेश्वरी रावत, पूर्व विधायक प्रत्याशी सरदार सिंह पुंडीर, नगर अध्यक्ष मुनि की रेती, महिपाल सिंह बिष्ट, नगर अध्यक्ष नरेंद्र नगर मनीष चौहान, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अनिल तड़ियाल, नगर अध्यक्ष शैलेंद्र गुसाई, महामंत्री पवन बिजलवान, विजय बलोदी, ललिता राणा, रेशमा, महिपाल बिष्ट, महिपाल पुंडीर, नागेंद्र पोखरियाल, कुंवर सिंह राणा, राकेश चौहान, प्रेम सिंह नेगी आदि मौजूद रहे।

अब और भी आसानी से मिल पायेगा सभी योजनाओं का लाभ: धामी

- मुख्यमंत्री ने मेरी योजना पोर्टल उत्तराखंड का लोकार्पण किया

भास्कर समाचार सेवा

कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा तैयार मेरी योजना पुस्तकों का लोकार्पण करते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सर्वे चौक स्थित आईआरडीटी ऑडिटोरियम में कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा तैयार की गई मेरी योजना पुस्तकों पर विचार गोष्ठी में प्रतिभाग किया।

इस अवसर पर उन्होंने मेरी योजना पोर्टल उत्तराखंड का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महत्वपूर्ण योजना मार्गदर्शिका पुस्तक के मेरी योजना, मेरी योजना-राज्य सरकार तथा मेरी योजना-केंद्र सरकार तीनों संस्करणों के माध्यम से राज्य का प्रत्येक नागरिक केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं की संपूर्ण जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकता है और उनका लाभ उठा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य योजनाओं का धरातल पर प्रभावी क्रियान्वयन के साथ ही उसका लाभ राज्य के प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक समयबद्ध रूप से पहुंचाना है। ये पुस्तकें लाभार्थियों को योजनाओं की संपूर्ण जानकारी प्रदान करने के साथ-साथ आवेदकों को आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज व पात्रता संबंधी जानकारी भी प्रदान करती है। जहां एक ओर राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, खेल, पेयजल और हवाई कनेक्टिविटी जैसे सभी प्रमुख क्षेत्रों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सभी से अपील की कि राज्य के स्थानीय उत्पादों और लोगों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों में प्रदान किये जाने वाले स्मृति चिन्ह राज्य में निर्मित उत्पादों के ही हों। उन्होंने कहा कि वे जब भी किसी कार्यक्रम में जाते हैं या देशभर में महानुभावों से भेंट के दौरान भी उत्तराखंड के स्थानीय उत्पाद ही भेंट करते हैं। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से यह एक सराहनीय प्रयास है।

एकीकृत पोर्टल के माध्यम से पात्र लोगों को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल पायेगा। सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन दीपक कुमार ने कहा कि कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग का मुख्य उद्देश्य योजनाओं और सेवाओं का सरल तरीके से लाभार्थियों तक पहुंचाना है।

डीएम ने धीमी गति से चल रहे कार्यों पर नाराज़गी जताई

सभी विभागों की ओर से मुख्यमंत्री घोषणाओं पर की गई प्रगति की विस्तृत जानकारी ली

भास्कर समाचार सेवा

मुख्यमंत्री घोषणाओं की विभागवार समीक्षा बैठक लेते जिलाधिकारी सविन बसंल।

देहरादून। जिलाधिकारी सविन बसंल ने ऋषिपर्णा सभागार में मुख्यमंत्री घोषणाओं की विभागवार समीक्षा बैठक ली। बैठक में डीएम ने सभी विभागों की ओर से घोषणाओं पर की गई प्रगति की विस्तृत जानकारी ली और लंबित मामलों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाएं प्राथमिकता वाले कार्य हैं, इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने विभागवार प्रस्तुतियों का अवलोकन करते हुए धीमी गति से चल रहे कार्यों पर नाराज़गी जताई और संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधार करने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान आवास, एमडीडीए, नगर निगम, खेल, युवा कल्याण आदि विभागों में भूमि चयन समस्या के कारण लंबित घोषणाओं पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि संबंधित एसडीएम के साथ समन्वय करते हुए समस्या का शीघ्र समाधान किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि दूसरे विभाग से संबंधित जिन घोषणाओं को स्थानांतरित किया जाना है उनका प्रस्ताव शीघ्र तैयार कर संबंधित विभागों को तत्काल उपलब्ध करें। सभी विभाग सीएम घोषणाओं की प्रगति को तत्काल रूप से ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि सीएम घोषणाओं में किसी प्रकार का कोई तर्क, वितर्क, देरी, लापरवाही क्षम्य नहीं है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले स्तर से जिन घोषणाओं पर कार्रवाई की जानी है, उनमें तत्काल और त्वरित गति से कार्य किया जाए। निर्माण कार्यो के लिए आंगणन गठित करते हुए टेंडर प्रक्रिया को शीघ्र पूरा कराया जाए। डीएम ने कहा कि जिला स्तरीय कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन घोषणाओं पर निर्णय या स्वीकृति शासन स्तर से अपेक्षित है, उन्हें संबंधित विभाग उच्च स्तर पर प्रभावी रूप से परस्यू करें, ताकि प्रक्रियाएं समय पर आगे बढ़ सकें। किसी कारण से जिन घोषणा को पूर्ण कराया जाना संभव नही हो पा रहा है, उन्हें शासन से स्वीकृति लेकर विलोपित किया जाए। शासन से स्वीकृत घोषणा को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। बैठक में विभिन्न विकास कार्यों, निर्माण परियोजनाओं, जनसुविधाओं के विस्तार और अवसंरचना से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की गई। बैठक में जानकारी दी गई कि जिले में मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2021 से अब तक कुल 491 घोषणाएं की गई। इसमें से 305 घोषणा पूर्ण कर ली गई है तथा 107 घोषणाओं में कार्य प्रगति पर है और 76 घोषणाओं में शासन एवं विभागीय स्तर कार्यवाही गतिमान है। जबकि तीन घोषणाओं को मर्ज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री घोषणाओं के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग की 10, आवास की 5, पेयजल की 7, शहरी विकास 12, समाज कल्याण की 10, विद्यालयी शिक्षा की 9, वन विभाग 4, पर्यटन 6, युवा कल्याण 4, पंचायती राज 3, बाल विकास 2 आदि पर घोषणाओं गतिमान है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. एमके शर्मा, सीईओ वीके ढौंडियाल, डीएसटीओ एसके गिरी सहित सभी अधिकारी मौजूद थे।

बासमती धान के पुनर्जीवन का संकल्प अब धरातल पर साकार

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुकी राजधानी की मशहूर दून बासमती धान के पुनर्जीवन का संकल्प अब धरातल पर साकार होता हुआ दिख रहा है। जिला प्रशासन की दूरदर्शी पहल ने इस पारंपरिक और सुगंधित धान को फिर से नई पहचान और नई ऊर्जा प्रदान की है। दून बासमती, जो कभी देहरादून की पहचान और किसानों की शान थी, कई वर्षों से घटते उत्पादन और आधुनिक किस्मों की आड़ में लगभग समाप्त होती दिख रही थी। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देशन और जिला प्रशासन की सक्रियता ने इस कीमती धान की पैदावार को फिर से जीवित किया है। जिला प्रशासन की सराहनीय पहल की बदौलत देहरादून के सहसपुर और विकास नगर के किसानों ने दून बासमती की टाइप-3 खेती/फसल को विस्तार दिया। वही नई पहचान के साथ अन्य किसानों को भी आगामी फसल के लिए प्रोत्साहित किया। किसानों के इस प्रयास ने न केवल इस पारंपरिक फसल को नई दिशा दी, बल्कि अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणास्रोत बन गया।

बड़ी सीवर लाइन डालने की मांग

हरिद्वार। उपनगरी ज्वालापुर क्षेत्र में सीवर उफनना सबसे बड़ी समस्या बन गया है। सीवर उफनने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। परेशानी झेल रहे क्षेत्र के लोग बड़ी सीवर लाइन बिछाने की मांग कर रहे हैं। बढ़ती आबादी छोटी लाइन सीवर बहने का प्रमुख कारण बनी हुई है।

सार्वजनिक सूचना

सूचित किया जाता है कि सम्पत्ति स्थित केदापुरम पछवादून तहसील देहरादून, उत्तराखण्ड जिसका खसरा नं. 60खमि व खाता सं. 00562 जो विधिवत रुप से दिनांक 14.12.2001 को दर्ज व पंजीकृत है जिसकी मूल रजिस्ट्री कहीं गुम हो गई है जो काफी तलाश करने पर भी नहीं मिली। जिस किसी को मिले कृपया सम्पर्क करें :

श्री रामस्वरुप जोशी
पुत्र स्व. विशम्बर जोशी
मोथरोवाला, जिला देहरादून, उत्तराखण्ड।

फॉर्म जी के लिए शुद्धिपत्र
रुचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण
गुप्ता पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
(दिवाला और दिवालियापन के विनियम 36ए(1) के तहत
(कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016

यह दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 और दिवाला और दिवालियापन (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के अनुसार जारी किए गए फॉर्म जी दिनांक 25/11/2025 के संदर्भ में है, रुचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति की अंतिम तिथि 7 (सात) दिनों के लिए बढ़ा दी गई है, तदनुसार फॉर्म जी और आईईओआई जारी करने के बाद की घटनाओं के लिए संशोधित तिथियां ।

क्र.सं.	प्रासंगिक विवरण	समयसीमा
10.	रुचि की अभिव्यक्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि	17 दिसंबर 2025 (10 दिसंबर, 2025 से विस्तारित)
11.	संभावित समाधान आवेदकों की अनंतिम सूची जारी करने की तिथि	27 दिसंबर 2025 (20 दिसंबर, 2025 से विस्तारित)
12.	अनंतिम सूची के आवेदकों पर आपत्ति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	02 जनवरी 2026 (26 दिसंबर, 2025 से विस्तारित)
13.	संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	07 जनवरी 2026 (30 दिसंबर, 2025 से विस्तारित)
14.	संभावित समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स और समाधान योजनाओं के लिए अनुरोध जारी करने की तिथि	10 जनवरी 2026 (03 जनवरी, 2026 से विस्तारित)
15.	समाधान योजनाएं जमा करने की अंतिम तिथि	10 फरवरी 2026 (03 फरवरी, 2026 से विस्तारित)
16.	EOI जमा करने के लिए प्रक्रिया ईमेल आईडी	ip.guptapower@gmail.com

नोटः दिनांक 25/11/2025 के फॉर्म जी की अन्य सामग्री और शर्तें समान रहेंगी ।

एसडी/-
सीए. प्रदीप कुमार काबरा
मेसर्स गुप्ता पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के लिए आरपी
आईबीबीआई पंजीकरण संख्याः IBBI/IPA-001/IP-P01104 /2017-18/11790
ईमेलः ip.guptapower@gmail.com

दिनांकः 11 दिसंबर, 2025
स्थानः सूरत

वोट चोरी से ही 2014 में गद्दी छोड़ने पर मजबूर हुई कांग्रेस: भट्ट

- पकड़ी गई सोनिया गांधी की वोट चोरी, कांग्रेस छुड़वाए अब उनसे पद

भास्कर समाचार सेवा

देहरादून। देहरादून। भाजपा ने कांग्रेस की रैली पर कटाक्ष कर कहा कि जनता ने तो कांग्रेस पार्टी को वोट चोरी पर ही 2014 से गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया है।

प्रदेशाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने दिल्ली जाने पर बाध्य कांग्रेसियों से सहानुभूति जताते हुए कहा कि उनकी सुप्रीमो सोनिया गांधी पर तो वोट चोरी का ताजा मामला न्यायालय में आया है। उन्होंने मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यह रैली अपने युवराज को गलत मुद्दे पर सही ठहराने की कांग्रेसी कोशिश है। क्योंकि जनता, आजादी से पहले से ही नेहरू, इंदिरा, राजीव, मनमोहन तक कांग्रेस पार्टी की वोट चोरी ही नही, डकैती भी भुगतती आई है। लिहाजा जैसे जैसे चुनाव प्रक्रिया में सुधार हुआ, नई नई तकनीकें आईं, कांग्रेस को बहुमत मिलना समाप्त हो गया था।

आखिरकार जनता की अदालत ने कांग्रेस पार्टी को वोट चोरी के इल्जाम में ही 2014 से ही गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया हुआ है। जो आज एसआईआर जैसी संवैधानिक प्रक्रिया पर वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं, उनकी सरकारों में ही 8 बार यह मतदाता सूची में सुधार की यह प्रक्रिया संपन्न हुई हैं। उन्होंने हाल दिल्ली कोर्ट में शुरू हुए वोट चोरी के केस का जिक्र करते हुए कहा कि सोनिया गांधी 1983 में देश की नागरिक बनने से पहले ही मतदाता बनकर वोट डाल रही थी।

एम्स में मल्टी ऑर्गन प्रत्यारोपण सर्जरी विभाग का अनुरोध

- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केन्द्रीय स्वास्थ्य नड्डा को लिखा पत्र

भास्कर समाचार सेवा

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को पत्र लिखकर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ऋषिकेश में मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी विभाग की स्थापना का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि विगत वर्षों में एम्स ऋषिकेश में उन्नत चिकित्सा सेवाओं की मांग अत्यन्त तीव्र गति से बढ़ी है, विशेषकर अंगदान एवं मल्टी ऑर्गन प्रत्यारोपण सर्जरी के क्षेत्र में। इसके कारण प्रदेश ही नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्यों से आने वाले गंभीर मरीजों की संख्या में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है।

उन्होंने उल्लेख किया कि अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ने से संभावित डोनर मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जबकि किडनी, लिवर, पैंक्रियाज एवं हृदय प्रत्यारोपण की आवश्यकता वाले मरीजों को अक्सर बाहरी राज्यों में जाना पड़ता है। इससे उपचार में देरी होती है और मरीजों को आर्थिक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि एम्स ऋषिकेश में विशेषज्ञ डॉक्टर, आवश्यक बुनियादी ढांचा एवं तकनीकी क्षमता उपलब्ध है, ऐसे में मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी विभाग की स्थापना से इस महत्वपूर्ण संस्थान की क्षमता और अधिक प्रभावी होगी। यह विभाग उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत और हिमालयी क्षेत्र के लिए अत्यन्त लाभकारी सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध किया है कि जनहित में एम्स ऋषिकेश में विभाग की स्थापना को स्वीकृति प्रदान करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

उत्तर रेलवे
निविदा सूचना
निविदा संख्या 23/2025 दिनांक : 09.12.2025

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (रु.)	कार्यालय का पता जहां से निविदा प्रपत्र जारी किया गया है	बिड सिक्यूरिटी (रु.)	कार्य के पूरा करने की समय अवधि	निविदा प्रपत्र जमा करने तथा खुलने की दिनांक व समय	वेबसाइट एवं कार्यालय का पता
1	27/वरिष्ठ मं.वि.अभि./सा./मुरा/2025: कोचिंग डिपो में विद्युत परिसंपत्तियों के रखरखाव और तकनीकी अवसंरचना का विस्तार तथा प्री–कूलिंग और चार्जिंग पॉइंट्स के लिए विद्युत कार्य एवं डाउन यार्ड मुरादाबाद में फ्रेट लोड के लिए लाइन संख्या 13 एवं 14 पर अंडर गियर जांच के लिए प्रकाश व्यवस्था एवं वेल्डिंग सुविधाओं का प्रावधान।	17630839.11 (जीएसटी सहित)	विद्युत शाखा, मंडल रेल प्रबन्धक कार्यालय, मुरादाबाद	238200.00	6 (छः) महीने	निविदायें दिनांक 31.12.2025 को 15:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है जो उसी दिन 15:00 बजे खोली जायेंगी।	वेबसाइट www.ireps.gov.in मण्डल रेल प्रबन्धक कार्यालय/ मुरादाबाद।
2	28/वरिष्ठ मं.वि.अभि./सा./मुरा/2025: एबीएसएस के लिए विद्युत कार्य: परिसंचारी क्षेत्र का उन्नयन, प्लेटफार्म संख्या 1 और 2/3 का उन्नयन, विस्तार और सीओपी, द्वितीय प्रवेश का विकास और धामपुर में एफओबी का विस्तार।	1852066.60 (जीएसटी सहित)		37100.00	6 (छः) महीने		
3	29/वरिष्ठ मं.वि.अभि./सा./मुरा/2025: एमबी के मौजूदा रनिंग रूम में प्रति कमरा दो बेड वाले 30 नए कमरों के निर्माण/संवर्द्धन में शेष विद्युत कार्य।	1754536.20 (जीएसटी सहित)		35100.00	6 (छः) महीने		

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ 3813/25

वरिष्ठ नागरिकों ने बसंत विहार पुलिस का आभार व्यक्त कर सम्मानित किया

देहरादून। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी अधीनस्थों को अपने-अपने क्षेत्र में निवास कर रहे बुजुर्ग व्यक्तियों तथा अकेले निवास कर रहे सीनियर सिटीजंस से समय समय पर मुलाकात कर उनकी समस्याओं के हर संभव निराकरण एव उनकी यथासंभव सहायता किये जाने को निर्देशित किया गया हैं। थाना बसंत विहार क्षेत्र में निवासरत सीनियर सिटीजनों द्वारा बुधवार को थाना बसंत विहार परिसर में एकत्रित होकर दून पुलिस द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए दून पुलिस की कार्यप्रणाली से संतुष्ट एवं प्रसन्न होकर दून पुलिस का आभार व्यक्त करते हुए उन्हे सम्मानित किया गया। इस दौरान थाने पर उपस्थित पुलिस टीम को सभी सीनियर सिटीजनों द्वारा अपना आशीर्वाद देते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य एवं उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस दौरान पुलिस टीम सभी बुजुर्गों की सुरक्षा एवं सेवा दून पुलिस की प्राथमिकता के संकल्प को दोहराते हुए विश्वास दिलाया कि दून पुलिस उनके सुख-दुःख में सदैव साथ खड़ी है।

सनातन भारत की शाश्वत धरोहर है मानवः चिदानन्द

ऋषिकेश। परमार्थ निकेतन में कथावाचक देवी चित्रलेखा अपने परिवार के साथ दर्शनार्थ आयी, उन्होंने स्वामी चिदानंद सरस्वती और साध्वी भगवती सरस्वती के सान्निध्य में आयोजित दिव्य गंगा आरती में सहभाग किया। गंगा तट पर सायंकालीन वातावरण अत्यंत दिव्य और भावपूर्ण था। मां गंगा की शीतल लहरों के बीच मंत्रों की पवित्र ध्वनि, दीपों की सुनहरी रोशनी और विश्व-मंगल की सामूहिक प्रार्थना ने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से ओत-प्रोत कर दिया। देवी चित्रलेखा ने अपने परिवार के साथ आरती में सहभाग कर अपनी मंत्रमुग्ध करने वाली वाणी में नाम संकीर्तन किया। स्वामी चिदानन्द सरस्वती ने कहा कि आज मानव अधिकार दिवस पर समूची मानवता को यह स्मरण कराना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि मानव गरिमा, स्वतंत्रता और समानता कोई आधुनिक अवधारणा नहीं है।

यूजेवीएन लिमिटेड
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
मुख्य कार्यालय "उज्जवल" महारानी बाग, जीएमएसयू रोड, देहरादून–248006, सिन नं: U40101UR2001SGC025866
दूरभाष सं0 0135–2763508, 2763808, फैक्सः 0135–2763507 वैबसाइटः www.ujvnl.com

सं0 965 **तिथि विस्तार सूचना** दिनांक 10.12.2025

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता (अनु0 एवं उत्पा0) ढालीपुर विद्युत गृह, द्वारा आमंत्रित निविदा सं0 **e-09/EE/M&G/DLR/2025-26** के सन्दर्भ मे निविदा जमा करने एवं निविदा खोलने की तिथियाँ अपरिहार्य कारणो से निम्नवत पुनरीक्षित की जाती हैः–
वेब पोर्टल पर निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि एवं समय : 15.12.2025 को समय 17:00 बजे तक
कार्यालय में कागजात जमा करने की अन्तिम तिथि एवं समय : 16.12.2025को समय 10:30 बजे तक
वेबपोर्टल पर निविदा खोलने की तिथि एवं समय : 16.12.2025 को समय 16:00 बजे
निविदा की अन्य नियम व शर्तपूर्ववत् रहेगी।
निविदा सम्बन्धित परिशिष्ठ/शुद्विपत्र/निरस्तीकरण आदि जानकारी वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।
अन्य जानकारी हेतु कृपया हमारी वेवसाइट देखें। निविदा प्रपत्र निगम की वेवसाइट **www.ujvnl.com** से डाउनलोड किये जा सकते है।

अधिशासी अभियन्ता
" बिजली के दुरूपयोग से बचें"

कार्यालय नगर निगम हरिद्वार

पत्रांकः-1527/नि०वि०/2025-26 दिनांक 09/12/2025

अति-अल्पकालीन निविदा सूचना

नगर आयुक्त महोदय एवं महापौर महोदया नगर निगम, हरिद्वार द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के क्रम में नगर निगम हरिद्वार द्वारा वर्ष 2025-26 में निगम क्षेत्रान्तर्गत निम्न तालिका में अंकित निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु नगर निगम हरिद्वार में पंजीकृत ठेकेदारों से सीलबन्द लिफाफों में निविदाएँ दिनांक 26.12.2025 को आमंत्रित की जाती है जो दिनांक 26.12.2025 को अपरान्ह 02:00 बजे तक डाली जायेगी एवं उसी दिन अपरान्ह 3:30 बजे गठित निविदा समिति एवं उपस्थित निविदादाताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र निर्माण अनुभाग, नगर निगम हरिद्वार कार्यालय से दिनांक 12.12.2025 से 18.12.2025 को अपरान्ह 1:00 बजे तक निर्धारित शुल्क जमा कराकर क्रय की जा सकती है। निविदा के साथ धरोहर धनराशि के रूप में भारत के किसी भी शेड्यूल बैंक द्वारा जारी एफ०डी०आर०/सी०डी०आर०/ टी०डी०आर०/राष्ट्रीय बचत पत्र जोकि वरिष्ठ वित्त अधिकारी, नगर निगम, हरिद्वार के पदनाम से बंधक हो, संलग्न करना अनिवार्य होगी। निविदा को बिना किसी सूचना के निरस्त करने का अधिकार अधिशासी अभियन्ता / नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम हरिद्वार में निहित होगा। निविदा से सम्बन्धित शर्ते एवं निविदा विक्रय की जानकारी नगर निगम, हरिद्वार कार्यालय निर्माण अनुभाग से किसी भी कार्य दिवस में देखी/प्राप्त की जा सकती है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	धरोहर धनराशि	निविदा की वैधता	निविदा का मूल्य 18% अतिरिक्त जी०एस०टी०	कार्य पूर्ण करने का समय
1	नगर निगम हरिद्वार वार्ड नं0-60 के हरिलोक फेज-2 सब्जी मंडी गेट नं0-2 के सामने इंटरलोकिंग टाईल्स लगाने का कार्य।	3,94000.00	11,820.00	60 दिन	500+जीएसटी	60
2	जगजीतपुर पीठ बाजार पुलिया के पास शौचालय निर्माण का कार्य।	6,00,000.00	18,000.00	60 दिन	1000+जीएसटी	60
3	जगजीतपुर क्षेत्र गुरूकुल दयानंद स्टेडियम में स्थित शौचालय निर्माण का कार्य।	6,00,000.00	18,000.00	60 दिन	1000+जीएसटी	60

अधिशासी अभियन्ता.
नगर निगम हरिद्वार।